

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF IRRIGATION
DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTARAKHAND IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.05.2025

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 417 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Ors

Respondents

INDEX

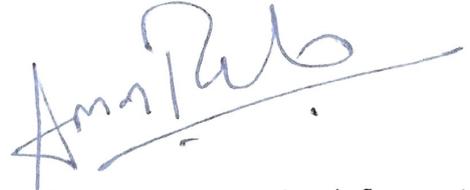
S.No	Particulars	Page No.
1	Compliance Affidavit on behalf of Irrigation Department, Government of Uttarakhand	3 - 6
2	<u>Annexure No. 1</u> : Final Notification dated 05.05.2025	7-8

3470

--	--	--

Place: Dehradun, Uttarakhand

Date: 14/8/2025



**Dr. Aman Rab, Advocate
(Counsel for Irrigation Department,
Government of Uttarakhand).**

3471

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

**COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF IRRIGATION
DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTARAKHAND IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.05.2025**

in

ORIGINAL APPLICATION NO. 417 OF 2022

IN THE MATTER OF:

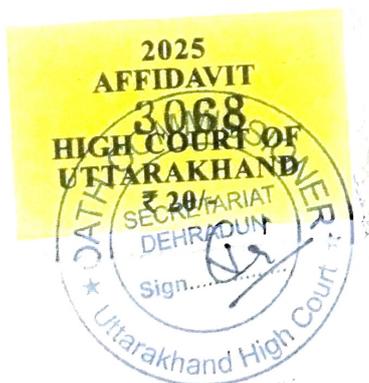
Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Ors

Respondents



Affidavit of Shri. Yugal Kishore Pant aged about 54 years S/o Shri. Gopal Datt Pant presently posted as Secretary, Irrigation Department, Government of Uttarakhand

Deponent



MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the above-mentioned matter was listed for hearing before the Learned Tribunal and the relevant extract of the directions passed by the Learned Tribunal vide order dated 27.05.2025 in so far as they pertain to the answering respondent are reproduced as follows:

“.....

8. So far as demarcation of flood plain zone of river Rispana is concerned, interim notification under section 8 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 was issued on 07.10.2024 and further progress report is to be filed.

9. The Secretary, Irrigation Department, Government of Uttarakhand is directed to file further progress report in this regard at least three days before the next date of hearing fixed.

.....”

2. That in compliance of the above, it is respectfully submitted that the final notification under the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 has been issued by the State Government. In this connection, the final notification dated 05.05.2025 is hereby being marked and filed as **Annexure No. 01** to this compliance report.
3. That furthermore, the process of demarcation has been completed in its entirety. The flood plain on either side of the river at different return periods (25 years and 100 years) has been duly marked. In this regard, 1808 pillars have been installed and the respective GPS coordinates have been duly recorded and mapped for future reference and monitoring.
4. That notice of the issuance of the final notification and completion of the demarcation process has been duly communicated to the higher authorities, including the District Magistrate, Dehradun; the Municipal Commissioner,



hu

3473

Dehradun; and the Vice-Chairman, Mussoorie Dehradun Development Authority (MDDA). The GPS coordinates of the 1808 installed pillars have also been provided to the said authorities in both hard copy and soft copy formats for record and necessary action.



Deponent

Verification: -

I, Mr. Yugal Kishore Pant, Secretary, Irrigation Department, Government of Uttarakhand, do hereby solemnly affirms and verify on oath that the contents of the accompanying Compliance Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false and no material has been concealed therein.



Deponent

Place: Dehradun

I, *Rushpendra S. Panwar*, presently posted as *Section Officer*, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be Mr. Yugal Kishore Pant is the same person who is known to me.



Identifier

Solemnly affirmed before me on this *14th* day of August, 2025 at about by the deponent who has been identified by the aforesaid advocate.



3474

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit, which has been read over and explained to him.

Dated: 14 August 2025



[Handwritten signature]

Signed, Sworn & Verified before me
by Shri/Smt. Xugal Kishor pant (Sec.)
Who is identified by Shri Pushpendra S. Panwal

Oath Commissioner

[Handwritten signature]
(VIKKI)
Oath Commissioner
High Court of Uttarakhand
(Secretariat Dehradun)
62/UHC/Admin.B/V-01/2025
Dt. 26-07-2025 to Dt. 25-07-2028
Sl. No. 3068 Date 14-08-25

[Handwritten signature]
(VIKKI)
Oath Commissioner
(Secretariat, Dehradun)

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2
संख्या: 327 /II(2)/2025-06(40)/2024
देहरादून, दिनांक: 01 मई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के अंतर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या: 941 / II(2) / 2024-06(40) / 2024, दिनांक: 07.10.2024 में संलग्न प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों की अनुसूची 01 और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:-

क्र.सं. क्षेत्र

अनुमन्य कार्यों का विवरण

1. प्रतिषिद्ध क्षेत्र
तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीडा, जल परिवहन, सेतु, ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां :
"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2. निर्बन्धित क्षेत्र
पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियां और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा। इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा :

"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, जिससे कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"



(Signature)

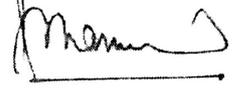
(डॉ० आर० सुजेश कुमार)
सचिव।

संख्या: 327 /II(2)/2025-06(40)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वन/शहरी विकास/राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्र प्राधिकारी, देहरादून।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC हरिद्वार की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

भाज्ञा से,



(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।



(VIKKI)

Oath Commissioner
High Court of Uttarakhand
(Secretariat Dehradun)
62/UHC/Admin.B/IV-01/2025
Dt. 26-07-2025 to Dt. 25-07-2028

Sl. No. 3068. Date. 14-08-25